

नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर भारत के बढ़ते कदम

डॉ ब्रजेश श्रीवास्तव

असिस्टेंट प्रोफेसर – अर्थशास्त्र

राजकीय महाविद्यालय मानिकपुर चित्रकूट

srivastavabrajesh6@gmail.com

शोध सारांश

आजकल भारत के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई-वॉलेट का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। कागजी नोट अभी भी हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग हैं। इससे पता चलता है कि नकदी रहित अर्थव्यवस्था काले धन, जाली मुद्रा, आतंकवाद, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने, नकदी से संबंधित अपराधों को कम करने और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देगी। यह नकदी आधारित अर्थव्यवस्था से नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में आने वाली चुनौतियों की भी पहचान करता है। प्रमुख चुनौतियां साइबर धोखाधड़ी, लोगों का रवैया, कमजोर बुनियादी ढांचा, डिजिटल भुगतान के उपयोग के बारे में जानकारी की कमी और नकदी रहित लेन-देन प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता की कमी हैं।

मुख्य शब्द: नकदी रहित अर्थव्यवस्था, नकदी रहित लेन-देन, डिजिटल भुगतान, काला धन, विमुद्रीकरण, साइबर सुरक्षा

I. INTRODUCTION

हाल के वर्षों में, "नकदरहित अर्थव्यवस्था" शब्द काफी चर्चित हो गया है, विशेष रूप से तकनीकी प्रगति और आर्थिक सुधारों के संदर्भ में। नकदरहित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जहाँ लेनदेन डिजिटल रूप से किए जाते हैं, सिक्कों या नोटों जैसी भौतिक मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता है। वित्तीय लेनदेन में दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता बढ़ाने की क्षमता के कारण इस प्रणाली ने भारत सहित दुनिया भर में काफी लोकप्रियता हासिल की है।

नकदरहित अर्थव्यवस्था के उद्देश्य

नकदरहित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण अक्सर रणनीतिक आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित होता है। इन उद्देश्यों में शामिल हैं:

- **नकदी पर निर्भरता कम करना:** नकदरहित अर्थव्यवस्था का प्राथमिक लक्ष्य भौतिक मुद्रा पर निर्भरता को कम करना है। डिजिटल भुगतान विधियों को बढ़ावा देकर, सरकारें और संस्थान वित्तीय लेनदेन को सुव्यवस्थित करने और नकदी की छपाई, वितरण और प्रबंधन से जुड़ी लागतों को कम करने का लक्ष्य रखते हैं।
- **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना:** नकदरहित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य वंचित आबादी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाती हैं।
- **भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश:** डिजिटल लेनदेन अधिक पारदर्शी और पता लगाने योग्य होते हैं, जिससे भ्रष्टाचार, कर चोरी और काले धन के प्रचलन जैसी अवैध गतिविधियों का फलना-फूलना मुश्किल हो जाता है। नकदी रहित प्रणाली वित्तीय नियमों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करती है।
- **आर्थिक विकास को बढ़ावा:** तेज और अधिक सुरक्षित लेनदेन को सक्षम बनाकर, नकदी रहित अर्थव्यवस्था व्यवसायों और उपभोक्ताओं को आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने में सहायता करती है। इससे समग्र आर्थिक विकास में योगदान होता है।
- **कर संग्रह में सुधार:** लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ने से कर अधिकारी कर योग्य आय को अधिक प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकते हैं, जिससे कर अनुपालन बेहतर होता है और सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है।
- **तकनीकी प्रगति को बढ़ावा:** नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण से नवीन भुगतान तकनीकों को अपनाने को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे डिजिटल अवसंरचना और साइबर सुरक्षा में प्रगति होती है।

नकदी रहित अर्थव्यवस्था का महत्व

नकदी रहित अर्थव्यवस्था का महत्व वित्तीय लेन-देन के तरीके को बदलने की इसकी क्षमता में निहित है। नकदी रहित अर्थव्यवस्था के महत्व के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:

- **आर्थिक दक्षता:** डिजिटल भुगतान नकदी लेनदेन से जुड़े समय और लागत को कम करते हैं, जैसे कि नकदी गिनना, जमा करना और निकालना। यह दक्षता व्यक्तियों, व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों सभी को लाभ पहुंचाती है।

- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** डिजिटल लेन-देन एक डिजिटल रिकॉर्ड छोड़ते हैं, जिससे वित्तीय गतिविधियों की निगरानी और लेखापरीक्षा करना आसान हो जाता है। यह पारदर्शिता आर्थिक प्रणाली में विश्वास और जवाबदेही को बढ़ावा देती है।
- **बढ़ी हुई सुरक्षा:** नकदी रहित अर्थव्यवस्था भौतिक नकदी ले जाने और भंडारण से जुड़े जोखिमों को कम करती है, जैसे कि चोरी और हानि। उन्नत एन्क्रिप्शन और प्रमाणीकरण प्रौद्योगिकियां डिजिटल लेनदेन को और अधिक सुरक्षित बनाती हैं।
- **सुविधा और सुलभता:** मोबाइल वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग और कॉन्टैक्टलेस कार्ड सहित डिजिटल भुगतान विधियां अद्वितीय सुविधा प्रदान करती हैं। लेनदेन कभी भी और कहीं भी पूरा किया जा सकता है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी लाभान्वित होती है।
- **पर्यावरणीय लाभ:** कागजी मुद्रा पर निर्भरता कम करने से कागज की मांग और नकदी छापने और वितरित करने में शामिल ऊर्जा-गहन प्रक्रियाओं को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान मिलता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैशलेस अर्थव्यवस्था का प्रभाव

नवंबर 2016 में नोटबंदी अभियान और उसके बाद डिजिटल भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के साथ भारत की नकदरहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की गति तेज हुई। इस परिवर्तन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा है-

- **डिजिटल लेनदेन में वृद्धि:** नोटबंदी के बाद, यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), पेटीएम, गूगल पे और अन्य जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों को अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस बदलाव ने लाखों भारतीयों को डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ दिया है।
- **वित्तीय समावेशन:** जन धन योजना जैसी पहलों और मोबाइल बैंकिंग के प्रसार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है। जिन व्यक्तियों को पहले बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं थी, वे अब डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग ले पा रहे हैं।
- **अर्थव्यवस्था का औपचारिककरण:** अधिक लेनदेन डिजिटल रूप से होने के कारण, अनौपचारिक क्षेत्र, जो पारंपरिक रूप से नकदी पर निर्भर था, धीरे-धीरे औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहा है। यह औपचारिककरण कर अनुपालन और सरकारी राजस्व को बढ़ावा देता है।

- **लघु व्यवसायों के लिए चुनौतियाँ:** जहाँ बड़े व्यवसायों ने डिजिटल भुगतान को अपना लिया है, वहीं कई लघु एवं मध्यम आकार के उद्यम (एसएमई) सीमित डिजिटल बुनियादी ढांचे और जागरूकता की कमी के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस अंतर को पाटना एक महत्वपूर्ण कार्य है।
- **डिजिटल भुगतान प्रणाली का विकास:** भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। विशेष रूप से यूपीआई ने वास्तविक समय में ग्राहकों और व्यापारियों के बीच लेन-देन को सुगम बनाकर एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान ने इस वृद्धि को और भी गति दी है।
- **नकदी प्रचलन में कमी:** जीडीपी के प्रतिशत के रूप में नकदी का प्रचलन कम हुआ है, जो डिजिटल भुगतान विधियों की ओर क्रमिक बदलाव का संकेत देता है। हालांकि, नकदी अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- **फिनटेक क्षेत्र में रोजगार सृजन:** डिजिटल भुगतान के उदय ने फिनटेक क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा दिया है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और वित्तीय प्रौद्योगिकियों में नवाचार को प्रोत्साहन मिला है।

नकदरहित अर्थव्यवस्था के लाभ

नकदरहित अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत और व्यापक आर्थिक स्तर पर अनेक लाभ प्रदान करती है:

- **सुविधा:** डिजिटल भुगतान विधियों से नकदी ले जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे लेन-देन सहज और परेशानी मुक्त हो जाता है।
- **लागत में कमी:** नकदी के प्रबंधन और संभालने की लागत में काफी कमी आती है, जिससे व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों को लाभ होता है।
- **बढ़ी हुई सुरक्षा:** डिजिटल भुगतान नकद लेन-देन की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं, जिससे चोरी, हानि और नकली मुद्रा से जुड़े जोखिम कम हो जाते हैं।
- **पारदर्शिता:** नकदरहित प्रणाली वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, जिससे भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के अवसर कम हो जाते हैं।
- **तेज़ लेन-देन:** डिजिटल भुगतान से धन का तत्काल हस्तांतरण संभव होता है, जिससे वित्तीय लेन-देन की दक्षता बढ़ती है।
- **कर राजस्व में वृद्धि:** लेन-देन की बेहतर निगरानी से सरकारें अधिक प्रभावी ढंग से कर एकत्र कर सकती हैं, जिससे सार्वजनिक राजस्व में वृद्धि होती है।

- **वित्तीय समावेशन:** डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वंचित आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं को सुलभ बनाते हैं, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई कम होती है।
- **नवाचार और विकास:** नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण भुगतान प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देता है और फिनटेक कंपनियों के विकास को प्रोत्साहित करता है।

नकदी रहित अर्थव्यवस्था के नुकसान

इसके लाभों के बावजूद, नकदी रहित अर्थव्यवस्था कई चुनौतियाँ और कमियाँ भी प्रस्तुत करती है:

- **डिजिटल विभाजन:** जनसंख्या के कुछ वर्गों में डिजिटल अवसंरचना और साक्षरता की कमी एक डिजिटल विभाजन का निर्माण करती है, जिससे वे नकदी रहित अर्थव्यवस्था में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं।
- **साइबर सुरक्षा जोखिम:** डिजिटल लेनदेन साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिनमें हैकिंग, डेटा उल्लंघन और फ़िशिंग हमले शामिल हैं। मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
- **प्रौद्योगिकी पर निर्भरता:** नकदी रहित अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर करती है, जिससे यह तकनीकी खराबी, बिजली कटौती या इंटरनेट कनेक्टिविटी समस्याओं के कारण होने वाली बाधाओं के प्रति संवेदनशील हो जाती है।
- **गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:** डिजिटल लेनदेन डेटा का रिकॉर्ड छोड़ते हैं, जिससे गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
- **परिवर्तन की लागत:** नकदी रहित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है, जो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक चुनौती हो सकती है।
- **बुजुर्गों और अशिक्षितों का बहिष्कार:** बुजुर्ग व्यक्तियों और सीमित शिक्षा वाले लोगों को डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपनाने में कठिनाई हो सकती है, जिससे सामाजिक बहिष्कार हो सकता है।
- **वित्तीय संस्थानों पर अत्यधिक निर्भरता:** नकदी रहित अर्थव्यवस्था बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं पर अधिक निर्भरता बढ़ाती है, जिससे एकाधिकारवादी प्रथाएं और उपभोक्ताओं के विकल्पों में कमी आ सकती है।

निष्कर्ष

नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना वित्तीय लेन-देन के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में, यह परिवर्तन उल्लेखनीय प्रगति से चिह्नित है, विशेष रूप से डिजिटल भुगतान

प्रणालियों को अपनाने में। नकदी पर निर्भरता कम करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य आर्थिक आधुनिकीकरण और विकास के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

हालांकि, नकदी रहित अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों, जैसे कि डिजिटल विभाजन, साइबर सुरक्षा जोखिम और कमजोर आबादी का बहिष्कार, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नीति निर्माताओं और हितधारकों को लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से इन मुद्दों का समाधान करना चाहिए, जैसे कि डिजिटल साक्षरता में सुधार, मजबूत साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश करना।

निष्कर्षतः, जबकि नकदी रहित अर्थव्यवस्था आर्थिक और सामाजिक लाभों के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करती है, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो समाज के सभी वर्गों की जरूरतों और क्षमताओं को ध्यान में रखे। जैसे-जैसे भारत नकदी रहित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, समावेशिता, सुरक्षा और नवाचार को बढ़ावा देना इसकी पूरी क्षमता को साकार करने की कुंजी होगी।

सन्दर्भ सूची

- [1]. Annamalai, S., & Iiakkuvan R. Muthu (2008). Retail Transaction: Future Bright for Plastic Money. Facts of You, 22-28.
- [2]. Deepika Kumari (2006). Cashless Transaction: Methods, Applications and Challenges. International Journal of Enhanced Research in Educational Development, 4 (6). Karamjeet Kaur, et al. (2016).
- [3]. E-Payment System on E-Commerce in India. Journal of Engineering Research and Applications, 5 (5), 63-73.
- [4]. Piyushkumar (2015). An Analysis of Growth Pattern of Cashless Transaction System. Impact Journals, 3 (9), 37-44.
- [5]. Saini, B.M. (2016). Demonetization – Metamorphosis for Cashless India. International Journal of Science and Research, 5 (12).
- [6]. Subramanian. S. (2014). Paper-free Payment Systems in India: An Analytical Study. International Journal of Management, 5 (1), 80-87.